My hunch is, there is pressure from the Clinton Administration.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Yes.

SHRI NARENDRA MOHAN: Madam, this point had been raised a number of times, through newspapers and otherwise. It is said that some officials of our embassy in Washington had assured the Clinton Administration that the Government of India was going to put the production of the Agni missile in cold storage, although the Government of India has not confirmed it.

I would, therefore, urge upon the Government through you, Madam, that there should be a definite statement from the Government of India whether such an assurance had been given. I am quoting from the US Government records. It is not based merely on newspaper reports. The US Government records say that our officers had asured them that Agni would be put in freeze. Now, this is something very, very serious. After all, the Standing Committee of Parliament had made certain observations on the production of the Agni missle. It was an unanimous view. If the unanimous view of the Parliament is going to be ignored by the Defence Ministry or any other Ministry of the Government of India, how far we are going to function as a democracy, or, as a Parliament? This is the basic question.

Madam, through you, I would urge upon the hon. Defence Minister and the hon. Prime Minister. The Prime Minister, in fact, holds the portfolio which deals with missile production. The Defence Ministry says that they need missiles. Either this has not been discussed in the Cabinet, or, this has been discussed but it has not been properly communicated to the other Ministry. These contradictions would definitely compromise our defence policy. I, therefore, urge upon the Government that there should be a statement from the Government on this issue. There should also be a proper debate on this.

उपसभापतिः श्री राजनाथ सिंह "सूर्य", आप बोलिये। मेरा सजेशन यह है कि आप "सूर्य" पहले ले आइए।

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': पहले तो लाना बड़ा मुश्किल है।

उपसभापतिः पहले "सूर्य" आ जाए, फिर राजनाथ आ जाए तो बड़ा आसान रहेगा।

श्री राजनाथ सिंह सूर्यः मैडम्...(व्यवधान)

उपसभापति : पहले सूर्य आ जाए फिर राजनाथ आ जाए तो आसानी होगी।

श्री राजनाथ सिंह सूर्यः इस पर विचार कर लेंगे आपसे, फिर जैसा होगा तय कर लेंगे।

उपसभापति : खाली सूर्य बोल दें।...(व्यवधान) एक ही सूर्य है इस पार्लियामेंट में।

श्री अजीत जोगीः एक ही सूर्य है, एक ही चमकेगा।

उपसभापति : डूबता भी है सूरज। इसलिए मैं राजनाथ सिंह जी को साथ में रखना चाहती हूं। हमारे हाऊस का सूर्य डूबना नहीं चाहिये किसी वक्त। ...(व्यवधान) बोलिए।

RE. ALLEGED INCREASING UNREST AMONG P.A.C. PERSONNEL FOR WANT OF RELIEF AFTER ACQUITTAL BY COURT

श्री राजनाथ सिंह सूर्य (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, मैं आपका ध्यान यह प्रश्न उठाने के पूर्व एक अन्य तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन के और दूसरे सदन के कई सदस्य छः दिसम्बर को एक ट्रेन से सफर कर रहे थे और उसकी 11 बोगियां ड्रेल हो गई थी। उस संबंध में भी मैंने एक सूचना दे रखी है और मैं समझता हूं कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसे भी उठाने का हमें अवसर दिया जाए।

उपसभापति : आपका तो कुछ और है यह।

श्री राजनाथ सिंह सूर्यः वह दूसरा है। उसको उठाने के पहले मैंने कहा कि उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपसभापति : जो दे रखा है उसके बारे में नहीं, जो आपको दे दिया है उसके बारे में कीजिए।

श्री राजनाथ सिंह सूर्यः मैडम, वह तो मैं उठाने जा रहा हूं।

महोदया, उत्तर प्रदेश में लगभग 23 वर्ष पहले पी०एस०सी० विद्रोह हुआ था। पुलिस प्रशासन में बड़ा असंतोष था और उस असंतोष के कारण वहां विद्रोह हुआ, कई स्थानों पर सेनाएं बुलानी पड़ी। सशस्त्र झड़पें भी हुई। कई पुलिसकर्मी उसमें मारे गये। पुलिस के कुछ अधिकारी भी मारे गए थे और परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि उस समय की जो सरकार थी उसके मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, उनके स्थान पर दूसरे मुख्य मंत्री नियुक्त हुए। पुलिस विद्रोह उस समय क्यों हुआ था उसका विशेष कारण था उनमें जो असंतोष था उस असंतोष के कारण पुलिस विद्रोह हुआ था। 23 वर्ष उन पर मुकदमा चला जो उस विद्रोह के अभियुक्त माने गये थे और 23 वर्ष बाद पिछले डेढ़ महीने उनके संबंध में एक अदालत का फैसला हुआ और अदालत ने उन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों से मुक्त कर दिए गए। इस बीच में जो पुलिस परिषद के पदाधिकारी थे, जो अन्य निम्न श्रेणी के पुलिसकर्मी थे, उनका बहुत ही उत्पीड़न हुआ और वह जगह-जगह न्याय के लिए दौड़ते रहे परन्तु उनको कहीं से भी न्याय नहीं मिला। अंततोगत्वा न्यायालय से उनको न्याय मिला। इस घटना की तरफ ध्यान आकर्षित करने का तात्पर्य पुनः पुलिस विद्रोह की संभावना का संकेत देना है। जब यह विद्रोह हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश में एक आई०जी० होता था और कुछ डी०आई०जी० होते थे और बाकी नीचे पुलिस अधिकारी होते थे। विद्रोह के बाद जो पुलिस प्रशासन में सुधार किया गया उसके फलस्वरूप आज लगभग 12 तो डी०जी० डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस हैं, 50 से अधिक आई०जी० हो गए, सैकड़ों डी०आई०जी० हो गए। यह पुलिस फोसर में टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन तो होता गया लेकिन नीचे के स्तर पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी न तो सेवा की शर्तों में सुधार हुआ और न जनसंख्या की वृद्धि और आवश्यकता के अनुसार उनको कोई सुविधा प्रदान की गई। जिन थानों में दस पुलिसकर्मी रहते थे आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि थानों में तो दो सौ से ढाई सौ तक पुलिसकर्मी रहते थे। न उनका मैस ठीक प्रकार से चलता है, न उनके खाने की व्यवस्था है। उनको 24 घंटे काम करना पड़ता है। इसके कारण से उनमें फिर से असंतोष पनप रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि वहां इस समय राष्ट्रपति शासन है, अगर उत्तर प्रदेश की इस स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो जो स्थिति 1973 में पैदा हुई थी उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। यह मसला बहुत गंभीर है और इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

RE. ALLEGED FELLING OF 300 TREES IN NUH FOR PRIME MINISTER'S SECURITY

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उप-सभापति महोदया, प्रधान मंत्री श्री देवगौड़ा जी अभी कुछ दिन पहले नूंह में गए थे और उनके नूंह में जाने पर वहां पर 300 पेड़ उनके हैलीकाप्टर को उतारने के लिए काट दिए गए। 300 पेड़ों में 120 साल पुराने मजेस्टिक शीशम का पेड़ था, दो 7 साल पुराने नीम थे, अस्सी 10 साल पुराने शीशम थे, अस्सी 2 साल पुराने यूकेलिप्टस थे, चालीस 5 साल पुराने सीमा पेड़ थे, पन्द्रह 12 साल पुराने अर्जुन पेड़ थे और पच्चीस 3 साल पुराने जामन के पेड़ थे। इन सारे पेड़ों को जो वहां पर 120-120 साल पुराने थे, हैलीकाप्टर उतारने के लिए काट दिए गए। प्रिंसिपल ने जो स्टेटमेंट दिया जिसके कालेज में यह हैलीपेड बनाया गया, उसने यह कहा कि: "These trees have survive the menance of floods but couldn't survive bureaucratic insensitivity. The area is flood-prone and every year, during the monsoon, the campus is waterlogged."

वहां पर सोलह किलोमीटर की दूरी पर सिविल एविएशन क्लब है जहां बड़ी आसानी से कोई भी जहाज उतर सकता है। वहां उतारने के बजाय कालेज को चुना गया और कालेज के सारे पेड़ इस तरीके से काटे गए। वहां के एक टीचर का स्टेटमेंट है—

> "If a Prime Minister's visit brings so much of destruction, we don't want such visits."

वहां के प्रिंसिपल का कहना है—

> "Not only our efforts but also our emotions were associated with these trees. Some of the trees had been planted by dignitaries visiting the college."

डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन ने अब उनसे कहा है कि आपका जो नुकसान हुआ है वह बताइए ताकि हम उसे पूरा कर सकें और प्रिंसिपल यह कहते हैं कि—

> "Nothing can compensate this green wealth."